*शाश्वत भविष्य के निर्माण के महत्वपूर्ण घटक : कुछ प्रतिबिंब**

शक्तिकान्त दास

मैं एक प्रख्यात सिविल सेवक श्री ललित दोशी की स्मृति में यह व्याख्यान देने के निमंत्रण के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। लगभग तीन दशक पहले कम उम्र में उनका आकस्मिक निधन होना महाराष्ट्र राज्य सहित कई लोगों के लिए एक बड़ी क्षति थी। श्री दोशी को उनके सहयोगियों और समकालीनों द्वारा विनम्र, शांत, मेहनती और अत्यंत सक्षम साथी के रूप में याद किया जाता है। 27 से अधिक वर्षों के अपने विशिष्ट सार्वजनिक सेवा कार्यकाल में, उन्होंने राज्य और केंद्र सरकारों, दोनों, में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1992-94 के दौरान महाराष्ट्र सरकार के उद्योग सचिव के रूप में, जनवरी 1994 में अपने दुखद निधन तक, उन्होंने राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री ललित दोशी और उद्योग सचिव के रूप में उनके द्वारा सामना की गई चुनौतियों का उल्लेख कर सकता हूं, क्योंकि मैंने दो अवसरों (2001 और 2006) पर तमिलनाडु सरकार के उद्योग सचिव के रूप में और 1991-1993 में संयुक्त सचिव, उद्योग के रूप में कार्य किया है।

1990 के दशक में उद्योगों के विघटन और आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद भारत में औद्योगिक क्षेत्र के लिए बहुत संभावनाएं थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए भारतीय रुपये का अवमूल्यन किया गया था। घरेलू और विदेशी निवेशकों ने अपने पदचिह्नों का विस्तार किया जिससे निवेश के नए अवसर खुले। बॉम्बे क्लब[1] को नई वास्तविकता को समायोजित करने में कुछ समय लगा, लेकिन समय के साथ बहुत अच्छी तरह से समायोजित किया गया। इस परिवेश में, राज्यों के बीच अपने मूल सिद्धांतों, सहायक बुनियादी ढांचे, कुशल जनशक्ति की गुणवत्ता और उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर निवेश आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी।

राज्य और देश के विकास और कल्याण में श्री ललित दोशी के योगदान को देखते हुए मैंने आज अपने संबोधन के विषय के रूप में 'शाश्वत भविष्य के निर्माण के महत्वपूर्ण घटक' को चुना है। शाश्वत भविष्य का अर्थ समावेशी और जलवायु के प्रति संवेदनशील रहते हुए मुद्रास्फीति के दबाव और अन्य व्यापक आर्थिक असंतुलन पैदा किए बिना अर्थव्यवस्था की विकास गति को बनाए रखना और मजबूत करना होगा। मैं आर्थिक विकास में एक केंद्रीय बैंक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करके और वर्तमान समष्टि आर्थिक संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए शुरू करना चाहूंगा और फिर एक शाश्वत भविष्य के लिए कुछ आधार स्तंभों को छूना चाहूंगा।

केंद्रीय बैंक और आर्थिक विकास

एक मजबूत और गतिशील केंद्रीय बैंक देश की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण निर्माण घटक के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय बैंकिंग की कहानी कम से कम 17 वीं शताब्दी से शुरू होती है, जब केंद्रीय बैंक के रूप में मान्यता प्राप्त पहली संस्था, स्वीडिश रिक्सबैंक, 1668 में बनाई गई थी। इसके बाद 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना।[2] हालांकि बागेहोट के सिद्धांतों के अनुसार केंद्रीय बैंकों की उत्पत्ति वाणिज्यिक बैंकों को अंतिम उपाय का ऋणदाता (एलओएलआर), सरकारों के लिए युद्ध वित्तपोषण, बार-बार की बैंक विफलताओं के बीच बैंकिंग स्थिरता बनाए रखने के कार्य के रूप में हुई, तथापि केंद्रीय बैंकों को बाद में बैंकनोट जारी करने और मुद्रा के आंतरिक और बाहरी मूल्य के प्रबंधन के कार्य सौंपे गए। उनकी भूमिका पिछले दशकों में लगातार विकसित हुई है, जो बदलते राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को दर्शाती है और अब वे आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।[3] 1990 के दशक और 2000 के

---

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा 23 अगस्त 2023 को वाई. बी. चव्हाण सेंटर, मुंबई में 29वें ललित दोशी स्मृति व्याख्यान में दिया गया भाषण।

1 बॉम्बे क्लब भारतीय व्यापारियों के एक समूह को संदर्भित करता है जो 1991 के संरचनात्मक सुधारों के बाद विदेशी प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा के लिए एकजुट हुए और विदेशियों के साथ समान अवसर के लिए की मांग की। (बिजनेस स्टैंडर्ड, 2013)।

2 माइकल डी. बोर्डो (2007), "केंद्रीय बैंकों का एक संक्षिप्त इतिहास", फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ क्लीवलैंड, दिसंबर।

3 "भारत में केंद्रीय बैंकिंग का विकास", मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2004-05, भारतीय रिज़र्व बैंक।

दशक की शुरुआत के दौरान, कई केंद्रीय बैंकों ने मूल्य स्थिरता उद्देश्य पर बारीकी से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के विनियमन की जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक के बाहर अलग-अलग विनियामकीय निकायों में स्थानांतरित हो गई। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) ने इस विकेंद्रण सिद्धांत पर पुनर्विचार किया और केंद्रीय बैंकों को अब मूल्य स्थिरता उद्देश्य के अलावा वित्तीय स्थिरता का कार्य अधिक सक्रिय रूप से सौंपा गया है। हाल ही में, कोविड-19 महामारी के दौरान, केंद्रीय बैंकों ने अपनी संबंधित अर्थव्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए जीएफसी के दौरान अपनाए गए परंपरागत और अपरंपरागत दोनों नीतियों का सहारा लिया।

भारत में केंद्रीय बैंकिंग का ढांचा, और विशेष रूप से मौद्रिक नीति, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934[4] के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों के अनुसार विकसित हुआ है। इसके अनुरूप, रिज़र्व बैंक की समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीति ने मूल्य स्थिरता बनाए रखने, संवृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने और वित्तीय स्थिरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित किया है। वित्तीय स्थिरता का उद्देश्य भारतीय वित्तीय प्रणाली और इसके विभिन्न क्षेत्रों, जिसमें धन, ऋण और विदेशी मुद्रा खंड और भुगतान और निपटान प्रणाली शामिल हैं, जिनके विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए रिज़र्व बैंक को शक्तियां प्रदान कर सक्षम किया गया है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा भंडार के रखरखाव, बैंक नोट जारी करने और मुद्रा प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन जैसे एजेंसी कार्यों, सरकार (केंद्र और राज्यों) के बैंकर और बैंकिंग प्रणाली के बैंकर के रूप में कार्य करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी बैंक के पास हैं। रिज़र्व बैंक के पास यह शक्तियां भी हैं कि जब भी आवश्यक हो वह अंतिम उपाय के ऋणदाता के रूप में कार्य कर सकता है। एक पूर्ण सेवाप्रदाता केंद्रीय बैंक के रूप में, यह वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। इन सभी क्षेत्रों में, हमने 1950, 1960 और 1970 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की शासन प्रभुत्व वाली प्रणाली से 1990 के दशक के बाद से एक बढ़ती बाजार अर्थव्यवस्था में संक्रमण के अनुरूप दशकों से अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत किया है।

1991 से शुरू हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने रिज़र्व बैंक की जिम्मेदारियों में कई नए आयाम जोड़े। वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के साथ-साथ, मौद्रिक नीति ढांचे को पिछले कुछ वर्षों में ठीक किया गया है, जिससे 2016 में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण रूपरेखा तैयार हुई है। पिछले तीन वर्षों में, हमने मौद्रिक नीति ढांचे में लचीलेपन का उपयोग कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभावों और यूक्रेन युद्ध का मुकाबला करने के लिए अपने कार्यों को मूल्यांकित करने के लिए किया है। कोविड-19 महामारी के दौरान, हमारी मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने दो महीने (मार्च-मई 2020) की अवधि में नीतिगत रेपो दर में संचयी रूप से 115 बीपीएस की कमी करके तेजी से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दरों में कटौती के साथ-साथ, हमने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने, विश्वास बहाल करने और बाजार गतिविधि को पुन:जीवित करने के लिए परंपरागत और अपरंपरागत दोनों उपायों के माध्यम से बड़ी मात्रा में चलनिधि उपलब्ध कराई, और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि हमारे चलनिधि बढ़ाने के उपायों से भविष्य में कोई प्रतिकूल स्थिति पैदा न हो।[5]

वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने की आवश्यकता को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने एक एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण संरचना विकसित करके बैंकों, एनबीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सुधार करने के लिए कई पहल की हैं। पर्यवेक्षी दृष्टिकोण अब कमजोरियों के मूल कारण को प्रभावी ढंग से निपटने और संभावित प्रणालीगत जोखिमों के किसी भी निर्माण की पहचान करने के लिए तैयार है। हम दबाव के प्रारंभिक संकेतों की पहचान करने और प्रारंभिक चरण में उनसे

[4] "भारत में मौद्रिक स्थिरता को सुरक्षित करने और आम तौर पर देश की मुद्रा और ऋण प्रणाली को भारत के हित के लिए संचालित करने की दृष्टि से बैंक नोट निर्गम को विनियमित करना और आरक्षित निधि बनाए रखना"। जैसा कि 2016 में धारा 45 जेड द्वारा संशोधित किया गया था, मौद्रिक नीति का उद्देश्य निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया था: "तेजी से जटिल होती अर्थव्यवस्था की चुनौती का सामना करने के लिए एक आधुनिक मौद्रिक नीति ढांचे का होना आवश्यक है; इस मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य संवृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना है; और भारत में मौद्रिक नीति ढांचे को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित किया जाएगा।

[5] फरवरी 2020 से मार्च 2022 के दौरान कुल मिलाकर ₹17.2 ट्रिलियन या जीडीपी के 8.7% चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा की गई।

निपटने के लिए सभी विनियमित संस्थाओं के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं। हम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं में अभिशासन और अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और लेखा परीक्षा के कार्यों में लगातार सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

रिज़र्व बैंक डेटा विश्लेषिकी का उपयोग करते हुए अपनी ऑन-साइट पर्यवेक्षी टीमों को बेहतर विश्लेषण जानकारी प्रदान करने के लिए समय-समय पर ऑफ-साइट विश्लेषण कर रहा है। एक *पूर्व चेतावनी ढांचा* (अर्ली वार्निंग फ्रेमवर्क) विकसित किया गया है। "दक्ष" नाम से एक नई सुपटेक पहल शुरू की गई है। विनियामकीय और पर्यवेक्षी स्टाफ के पर्यवेक्षी कौशल के उन्नयन के लिए एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) की स्थापना की गई है। हाल ही में, हमने एक केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) प्रारंभ किया है जो हमारी अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस है। डिजिटल भुगतान उत्पादों में जोखिमों को दूर करने के लिए *डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण दिशानिर्देश* जारी किए गए हैं। डिजिटल ऋण, जो एक उभरता हुआ क्षेत्र है, के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं । वास्तव में, यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 4 से 5 वर्षों में वित्तीय क्षेत्र की लगभग पूरी विनियामकीय और पर्यवेक्षी संरचना का पुनर्गठन किया गया है।

इन सुधारों को आगे बढ़ाते हुए, रिज़र्व बैंक ने बाह्य स्थिरता बनाए रखते हुए और विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करके प्रणालीगत समुत्थानशीलता और दक्षता में सुधार करने के लिए सक्रिय होकर प्रयास भी किए हैं। क्रियाशील वित्तीय बाजारों का विकास भी एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। ये सुधार, अन्य बातों के अलावा, बाजार भिन्नता को दूर करने, गैर-निवासियों सहित अधिक पहुंच की सुविधा प्रदान करने, भागीदारी आधार को व्यापक बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और ग्राहक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। अत्याधुनिक बाजार बुनियादी ढांचा स्थापित करने, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) पायलट की शुरुआत और रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए भी उपाय किए गए हैं। डिजिटलीकरण के सर्वोत्तम लाभों का उपयोग करके कोविड संकट को एक अवसर में बदल दिया गया है।

रिज़र्व बैंक, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं ऐसी और कई अन्य पहलों के लिए धन्यवाद की पात्र हैं जिनकी वजह से भारत का वित्तीय क्षेत्र समुत्थानशील और स्वस्थ बना हुआ है। इसके बावजूद, आत्मसंतोष के लिए कोई जगह नहीं है। नई चुनौतियां और तनाव के क्षण सामने आते रहेंगे, अत: सभी हितधारकों को उभरते घटनाक्रमों और संबंधित जोखिमों से अवगत रहने की जरूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था - वर्तमान संरचना

भविष्य के विकास के लिए निर्माण खंडों की पृष्ठभूमि के रूप में, मैं वैश्विक वातावरण से शुरू होने वाले वर्तमान व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर संक्षेप में बात करना चाहूंगा। वैश्विक परिदृश्य में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन देखे जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया धीमी हो गई है और बहुपक्षवाद से द्विपक्षीयता और भू-आर्थिक विखंडन की ओर बढ़ रही है। फ्रेंड-शोरिंग और रिशोरिंग अधिक प्राथमिकता प्राप्त हो गए हैं। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएं दबाव में हैं जिसके प्रभाव से, और बढ़ती वैश्विक वस्तुओं की कीमतों के कारण मुद्रास्फीति 2022 में दशकों की उच्च स्थिति में पहुंच गई है। इसके परिणामस्वरूप आक्रामक मौद्रिक सख्ती ने वैश्विक संवृद्धि दृष्टिकोण को संकुचित कर दिया है। तंग वित्तीय स्थिति और अस्थिर पूंजी प्रवाह उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संभावनाओं पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। हेडलाइन मुद्रास्फीति अब अलग-अलग देशों में असमान रूप से कम हो रही है, लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। मौद्रिक सख्ती की गति कम है, लेकिन कई देशों में नीतिगत दरें लंबे समय तक अधिक रह सकती हैं। हार्ड लैंडिंग की गंभीर संभावनाएं कम होने के बावजूद, मध्यम अवधि में ऐतिहासिक मानकों के अनुसार वैश्विक संवृद्धि कम रहने की संभावना है। बढ़ते जलवायु परिवर्तन जोखिमों के साथ, जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और टिकाऊ कृषि प्रथाओं का विकास हमारे भविष्य को आकार देगा। इन मोर्चों पर प्रगति की गति तेज करने की जरूरत है।

ऐसे अस्थिर वैश्विक माहौल के बीच, भारत दुनिया के लिए विकास के उभरते नेतृत्व के रूप में खड़ा है। भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ने 2022-23 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो महामारी से पहले के स्तर से 10.1 प्रतिशत

अधिक है। कुल मिलाकर 2023-24 में संवृद्धि की रफ्तार जारी रहने और पूंजीगत व्यय चक्र के गति पकड़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अवसर अब आशाजनक हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को उच्च संवृद्धि पथ पर ले जाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

इसके बावजूद उच्च मुद्रास्फीति की चुनौती अभी भी बनी हुई है और इससे प्रभावी ढंग से निपटने की आवश्यकता है। हेडलाइन मुद्रास्फीति मई 2023 में 4.3 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंचने के बाद, टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमतों में वृद्धि के कारण जुलाई में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गई। एमपीसी की बैठक के बाद जारी जुलाई प्रिंट हमारे अनुमानों की तुलना में अधिक था। सब्जियों की कीमतों में सालाना आधार पर 37.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें टमाटर की कीमतों में 201.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन कारणों से खाद्य समूह की मुद्रास्फीति जून के 4.7 प्रतिशत से बढ़कर जुलाई में 10.6 प्रतिशत हो गई। अनुकूल बात यह रही कि खाद्य और ईंधन (मुख्य मुद्रास्फीति) को छोड़कर मुद्रास्फीति जनवरी 2023 में अपने हालिया शिखर से गिरकर लगभग 130 बीपीएस नरम हो गई। हालांकि यह अभी भी 4.9 प्रतिशत तक बढ़ी हुई है, लेकिन पिछले पांच महीनों में मुख्य मुद्रास्फीति में यह लगातार कमी मौद्रिक नीति के चल रहे संचरण का संकेत है।

कालांतर में, जुलाई में सब्जियों की कीमतों में तेजी से सुधार दिखना शुरू हो हुआ, जिसकी अगुवाई टमाटर की कीमतों ने की। मंडियों में टमाटर की नई आवक पहले से ही कीमतों में नरमी ला रही है, साथ ही प्याज के मामले में सक्रिय आपूर्ति प्रबंधन भी है। हमें सितंबर से सब्जियों की मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय मंदी देखने की उम्मीद है। इस बीच, जुलाई में बेहतर मानसून के कारण *खरीफ* फसलों के लिए संभावनाओं में सुधार हुआ है, हालांकि कुल वर्षा फिर से ऋणात्मक स्थिति में चली गई है।[6] आपूर्ति पक्ष के सक्रिय उपायों के कारण अनाज की कीमतों के लिए दृष्टिकोण तदनुसार उज्ज्वल हो गया है। तथापि, आकस्मिक मौसमी घटनाएं, *अल नीनो* स्थिति और नए सिरे से शुरू हुए भू-राजनीतिक तनाव, खाद्य कीमतों के दृष्टिकोण में अनिश्चितता लाते हैं। जैसा कि मैंने 10 अगस्त 2023 को अपने मौद्रिक नीति वक्तव्य में उल्लेख किया था, सब्जियों की कीमतों के आघातों की संभावित अल्पकालिक प्रकृति को देखते हुए, मौद्रिक नीति ऐसे आघातों के पहले दौर के प्रभावों के प्रसार की प्रतीक्षा कर सकती है जो हेडलाइन मुद्रास्फीति में अल्पकालिक वृद्धि पैदा कर सकते हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क हैं कि कहीं यह वृद्धि सामान्य न हो जाए और दृढ़ न बने और इसके दूसरे क्रम के प्रभाव हावी न हो जाएं। बार-बार खाद्य कीमतों के आघातों की लगातार घटनाएं मुद्रास्फीति की उम्मीदों को कम करने के लिए जोखिम पैदा करती हैं, जो सितंबर 2022 से चल रही हैं। हम इस पर भी नजर रखेंगे। ऐसे आघातों की गंभीरता और अवधि को सीमित करने में निरंतर और समय पर आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप की भूमिका महत्वपूर्ण है। इन परिस्थितियों में, मूल्य स्थिरता के लिए किसी भी जोखिम से सतर्क रहना और उचित तथा समय पर कार्रवाई करना आवश्यक है। हम मुद्रास्फीति को 4.0 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रखने पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

शाश्वत भविष्य के लिए निर्माण के घटक

वर्तमान संदर्भ का एक संक्षिप्त ब्योरा प्रस्तुत करने के बाद, मैं अब कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर मुड़ना चाहूंगा जो अगले 25 वर्षों में भारत को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत के लिए अपने संवृद्धि पथ को बढ़ाने और लोगों के सामान्य कल्याण में सुधार करने की क्षमता बहुत अधिक है। इस संदर्भ में, मैं छह प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा जो आवश्यक संवृद्धि गति प्रदान कर सकते हैं। वे हैं (i) कृषि; (ii) विनिर्माण; (iii) सेवाएं; (iv) जनसांख्यिकी; (v) प्रौद्योगिकी; और (vi) स्टार्ट-अप। इन सभी क्षेत्रों में, हमारे पास पहले से ही कुछ तुलनात्मक लाभ हैं जिनका हमारी संवृद्धि सीमा को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। अब मैं इन क्षेत्रों पर एक-एक करके बात करूंगा।

(i) कृषि

दुनिया के भू-क्षेत्र का केवल 2.4 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत विश्व स्तर पर शीर्ष पांच कृषि उत्पादकों में से एक है।[7] भारतीय कृषि व्यापक कृषि-पारिस्थितिक क्षेत्रों के साथ विशाल विविधता का प्रतीक है। भारत न केवल खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, बल्कि खाद्यान्नों का शुद्ध निर्यातक भी है। फिर भी,

[6] 21 अगस्त 2023 तक संचयी दक्षिण-पश्चिम वर्षा सामान्य से 7 प्रतिशत कम है।

[7] पाठक एच., मिश्रा जेपी और महापात्र टी. (2022)। स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), नई दिल्ली।

भारत में कृषि क्षेत्र उत्पादकता अंतराल, बदलती प्राथमिकताओं और आकस्मिक मौसमी घटनाओं की चुनौतियों का सामना करता है। इन सभी के लिए बुनियादी ढांचे और नवाचार में भारी निवेश की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र को आधुनिक बनाया जा सके और उच्च उत्पादकता प्राप्त करने, बाजारों तक अधिक कुशल पहुंच प्रदान करने और किसानों की आय को अधिकतम करने के मामले में इसकी वास्तविक क्षमता का उपयोग किया जा सके। एक राष्ट्र के रूप में हमें विशेष रूप से कृषि विपणन और संबंधित मूल्य शृंखलाओं के क्षेत्र में अत्यावश्यक कृषि सुधारों को पूरा करने का एक तरीका खोजना चाहिए। ये सुधार न केवल शाश्वत उच्च संवृद्धि के लिए बल्कि किसानों की आय, टिकाऊ मूल्य स्थिरता और खाद्य मूल्य के आघातों की आवृत्ति और तीव्रता को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो हमने हाल के महीनों में देखा है। कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं, मेगा फूड पार्कों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना और सुधार की दिशा में नीतियां बनाना कृषि क्षेत्र के नुकसान को कम करने और मूल्य वर्धन में सुधार करने के लिए सही दिशा में कदम होंगे।

(ii) विनिर्माण

विनिर्माण क्षेत्र अपनी विशेषताओं जैसे कि उच्च उत्पादन पैमाने की अर्थव्यवस्था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और वैश्विक आपूर्ति शृंखला के एकीकरण के कारण आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विनिर्माण भी सेवाओं के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है। दोनों क्षेत्र संवृद्धि के लिए एक-दूसरे के लिए पूरक हैं। संवृद्धि के पारंपरिक प्रतिमान के विपरीत, जिसमें एक अर्थव्यवस्था कृषि से निकल कर विनिर्माण और फिर सेवाओं में बदल जाती है, भारत सीधे कृषि से सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था में छलांग लगा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 18-19 प्रतिशत पर स्थिर बनी हुई है।

विनिर्माण क्षेत्र के बदलते परिदृश्य में, भारत में एयरोस्पेस और रक्षा, कम कार्बन प्रौद्योगिकियों, इलेक्ट्रिक वाहनों और अर्धचालकों जैसे उभरते क्षेत्रों का लाभ उठाने की क्षमता है। भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों और लिथियम रीसाइक्लिंग क्षमताओं में प्रगति करते हुए उभरते क्षेत्रों में विनिर्माण कौशल का निर्माण करने के लिए सुधारों की शुरुआत की है। इस संबंध में, देश में उपलब्ध खनिज संसाधनों का सतत दोहन करने के लिए चल रहे खनन सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर, बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रौद्योगिकी अपनाने, कार्यबल के प्रशिक्षण और कौशल और डिजिटल प्रगति के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को अपनाना महत्वपूर्ण है।

(iii) सेवाएं

हाल के दशकों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में भारत के उद्भव में काफी हद तक इसके सेवा क्षेत्र के तेजी से विकास का योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवाओं का योगदान 2014-15 से 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। भारत 2022 में वैश्विक स्तर पर 7 वें सबसे बड़े सेवा निर्यातक के रूप में उभरा है, जो 2001 में 21 वें स्थान पर था। भारत ने वैश्विक सेवा नेटवर्क स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) सेवाओं के लिए यह एक वैश्विक केंद्र बन गया है। वैश्विक मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) में भारत की भागीदारी और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए नए अवसरों का उपयोग किया गया है।

पर्यटन, शिक्षा, दूरसंचार, जनोपयोगी सेवाएं और स्वास्थ्य देखभाल जैसे सेवा उद्योग महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। सड़क परिवहन और निर्माण सेवाओं जैसी गतिविधियों में उच्च रोजगार तीव्रता के साथ-साथ सर्वाधिक बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हैं। जीएसटी लागू होने के बाद इन सेवाओं को बढ़ावा मिला है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) स्थापित करने के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण भारत का व्यापार सेवाओं का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।[9] इंटरनेट बुनियादी ढांचे, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी सेवाओं का विकास और प्रावधान विभिन्न

[8] "मेक इन इंडिया" अभियान, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, कॉरपोरेट करों में कमी, व्यापार सुलभता में सुधार, एफडीआई नीति में सुधार, सार्वजनिक खरीद आदेशों के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय और चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) जैसे हाल के सरकारी नीतिगत उपाय समय पर किए गए हैं और विनिर्माण क्षेत्र में प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं।

[9] जीसीसी आईटी सहायता, लेखा सेवाएं, विधिक सेवाएं, व्यापार परामर्श, संचालन, क्षमता विकास और अनुसंधान सेवा प्रदान करते हैं।

उद्योगों के डिजिटल परिवर्तन और विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण हैं। भारत इन अवसरों का लाभ उठाने और अधिक कौशल-गहन और तेजी से डिजिटलीकृत सेवाओं को पूरा करने के लिए अच्छी स्थिति में है।

(iv) जनसांख्यिकी

भारत में वैश्विक कामकाजी उम्र की आबादी का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा है, और अगले तीन दशकों में कामकाजी उम्र में 183 मिलियन लोगों के जुड़ने की उम्मीद है।[10] वर्ष 2030 तक भारत के लिए औसत उम्र 30 वर्ष से कुछ अधिक रहने की संभावना है।[11] इस जनसांख्यिकीय लाभ को देखते हुए, भारत विश्व स्तर पर श्रम आपूर्ति की प्रत्याशित कमी के बीच मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, और माल और सेवाओं के लिए उभरती मांगों के अनुकूल होने में सक्षम एक संपन्न बाजार भी होगा। इससे भारत के पक्ष में विकास अंतर में सुधार हो सकता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के सापेक्ष आकार में वृद्धि हो सकती है। विकसित होते जनसांख्यिकीय प्रोफाइल से प्रेषण की मात्रा के साथ-साथ गुणवत्ता में भी पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है। पहले कम-कुशल और अनौपचारिक रोजगार के लिए लोग भारत से खाड़ी देशों में जाते थे। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय प्रवासियों के प्रमुख गंतव्यों में धीरे-धीरे संरचनात्मक बदलाव आया है। अब बड़े पैमाने पर लोग भारत से उच्च आय वाले देशों में जाते हैं और वे उच्च-कौशल की नौकरियों का एक प्रमुख हिस्सा हैं। 2022-23 में आवक विप्रेषण 112.5 बिलियन यूएस डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और यह सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है। आने वाले समय में, प्रौद्योगिकीय सफलताओं, ऊर्जा संक्रमण और भू-अर्थशास्त्र द्वारा संचालित श्रम बाजार परिवर्तन भारत को अपनी प्रवासी आबादी से सीमा पार लाभ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण शक्ति स्रोत बनने जा रहे हैं।

हमारी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए श्रम बल की भागीदारी दर, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी दर में सुधार करना महत्वपूर्ण है।[12] हमारे जनसांख्यिकीय लाभ को उपयोग में लाने के लिए शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने की आवश्यकता है। नवाचार और सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे पर निरंतर और अधिक ध्यान देने से श्रम उत्पादकता, भारत की संभावित संवृद्धि और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सकती है।

(v) प्रौद्योगिकी

दुनिया एक प्रौद्योगिकीय क्रांति के मुहाने पर खड़ी है। ऐसे में भारत के लिए खुद को डिजिटल-आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का यह उपयुक्त समय है। प्रौद्योगिकीय प्रगति ने न केवल महामारी के वर्षों के दौरान आभासी शिक्षा, दूरस्थ कार्य और संपर्क रहित बिक्री को सक्षम किया है, बल्कि कुशल लोक वितरण में भी सहायता की है और समग्र उत्पादकता संवृद्धि के लिए एक बड़े प्रोत्साहन के रूप में कार्य किया है।[13]

भारतीय कारोबार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और बिग डेटा जैसी अग्रणी प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाने में अग्रणी होना जरूरी है। एक युवा और कुशल कार्यबल, एक गतिशील और फुर्तीला पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत सार्वजनिक डिजिटल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के साथ, यह भारतीय कारोबार के लिए विकास का एक अच्छा चक्र स्थापित कर सकता है। इस दशक को भारत के 'डिजिटल दशक' के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें देश 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की उपभोक्ता इंटरनेट अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए तैयार है।[14]

रिज़र्व बैंक संरक्षित, सुरक्षित, तेज़, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती ई-भुगतान विकल्पों में लगातार सुधार करके उन्हें सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। रिज़र्व बैंक डिजिटल वित्तीय क्षेत्र में सुरक्षित और समावेशी विकास में सहयोग देने के लिए सबसे आगे रहा है।[15]

---

[10] आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)

[11] इसके विपरीत, विकसित अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बुढ़ापे का सामना कर रही हैं, अनुमान बताते हैं कि 2047 तक उनकी 25-30 प्रतिशत आबादी 60 वर्ष से ऊपर होगी (मैकिन्से-फिक्की रिपोर्ट)। 2030 तक, चीन और अमेरिका के लिए औसत आयु लगभग 40 (वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम) होने की उम्मीद है।

[12] India@100, आरबीआई बुलेटिन, जून 2023।

[13] यह तथ्य भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में देखा गया, जहां 2021 में औद्योगिक रोबोट की संस्थापना में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[14] गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी की 'ई-कोनोमी इंडिया 2023: एक बिलियन से जुड़े भारतीयों की अर्थव्यवस्था' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट, जून 2023।

[15] उपायों में 2016 में एकाउंट एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2017 में पीयर-टू-पीयर (पी 2 पी) ऋण के लिए नियम, 2019 में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए विनियामकीय सैंडबॉक्स ढांचे का शुभारंभ, 2021 में आरबीआई इनोवेशन हब की स्थापना और 2022 में केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (ई-₹) का पायलट शामिल है।

यूपीआई को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती खुदरा भुगतान प्रणाली के रूप में माना जाता है। कई देशों ने यूपीआई जैसी प्रणाली में रुचि व्यक्त की है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ मिलकर सिंगापुर, भूटान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और कई अन्य देशों में यूपीआई को शीघ्र भुगतान प्रणालियों के साथ जोड़ने में रिज़र्व बैंक की पहल आने वाले वर्षों में यूपीआई की उच्च क्षमता को प्रदर्शित करती है। आरटीजीएस की 24*7*365 आधार पर उपलब्धता ने भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में निपटान और ऋण जोखिमों को कम करने में मदद की है। इस विशिष्ट सुविधा को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था।

(vi) नवाचार और स्टार्ट-अप

नवाचार दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख घटक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में हाल ही में मिली सफलता किसी बिगटेक कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि एक स्टार्ट-अप, यानी ओपनएआई की थी, जो प्रौद्योगिकी संचालित आर्थिक समृद्धि लाने में स्टार्ट-अप की शक्ति के बारे में काफी कुछ बताती है।[16] यह उत्साहजनक बात है कि कई स्टार्ट-अप छोटे और मध्यम व्यवसायों, वित्तीय समावेशन, सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, बेहतर शिक्षा और उच्च आय पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।[17]

क्वांटम कंप्यूटिंग, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर), एआई-आधारित रक्षा उपकरण, जैव प्रौद्योगिकी, रेअर अर्थ एक्सट्रेक्शन, बैटरी प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे उच्च तकनीक क्षेत्रों में स्टार्ट-अप के लक्षित विकास के लिए अब समय आ गया है। देश की प्रगति की रफ़्तार बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों को शामिल करने वाले स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

संक्षेप में

अब मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे भारत की विकास गाथा सावधानी और सतर्कता को छोड़ आशावाद और उत्साह में बदल रही है, भारत के लिए अब उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी छाप छोड़ने का समय आ गया है। हाल ही में एक मीडिया लेख में भारत की क्षमता को उपयुक्त रूप से दर्शाया गया है: "वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक नए पावरहाउस की आवश्यकता है, भारत इसमें आगे है" (दी ग्लोबल इकॉनोमी नीड्स ए न्यू पॉवरहाउस, इंडिया इज स्टेपिंग अप)।[18] समय की मांग है कि आज मेरे भाषण में उल्लिखित क्षेत्रों और कुछ अन्य क्षेत्रों में भी ठोस प्रयास किए जाएं ताकि इस नए पावरहाउस - भारत की नींव रखी जा सके - जो आकार, आत्मविश्वास और समावेशिता में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

धन्यवाद। नमस्कार।

[16] आज, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र (https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1913106) है और यहां 99,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप (https://www.startupindia.gov.in/ 22 जुलाई 2023 के अनुसार) हैं। भारत के टेक स्टार्टअप्स ने कैलेंडर वर्ष 2022 में 18.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए (इंडिया टेक स्टार्ट-अप लैंडस्केप रिपोर्ट 2022, नैसकॉम और जिनोव), और भारत ने इस साल अपनी तालिका में 23 यूनिकॉर्न जोड़े, जो अमेरिका के बाद दूसरा सबसे अधिक है।

[17] इंडिया टेक स्टार्ट-अप लैंडस्केप रिपोर्ट 2022, नैसकॉम और जिनोव

[18] https://www.bloomberg.com/news/features/2023-01-23/india-s-1-4-billion-population-could-become-world-economy-s-new-growth-engine#xj4y7vzkg